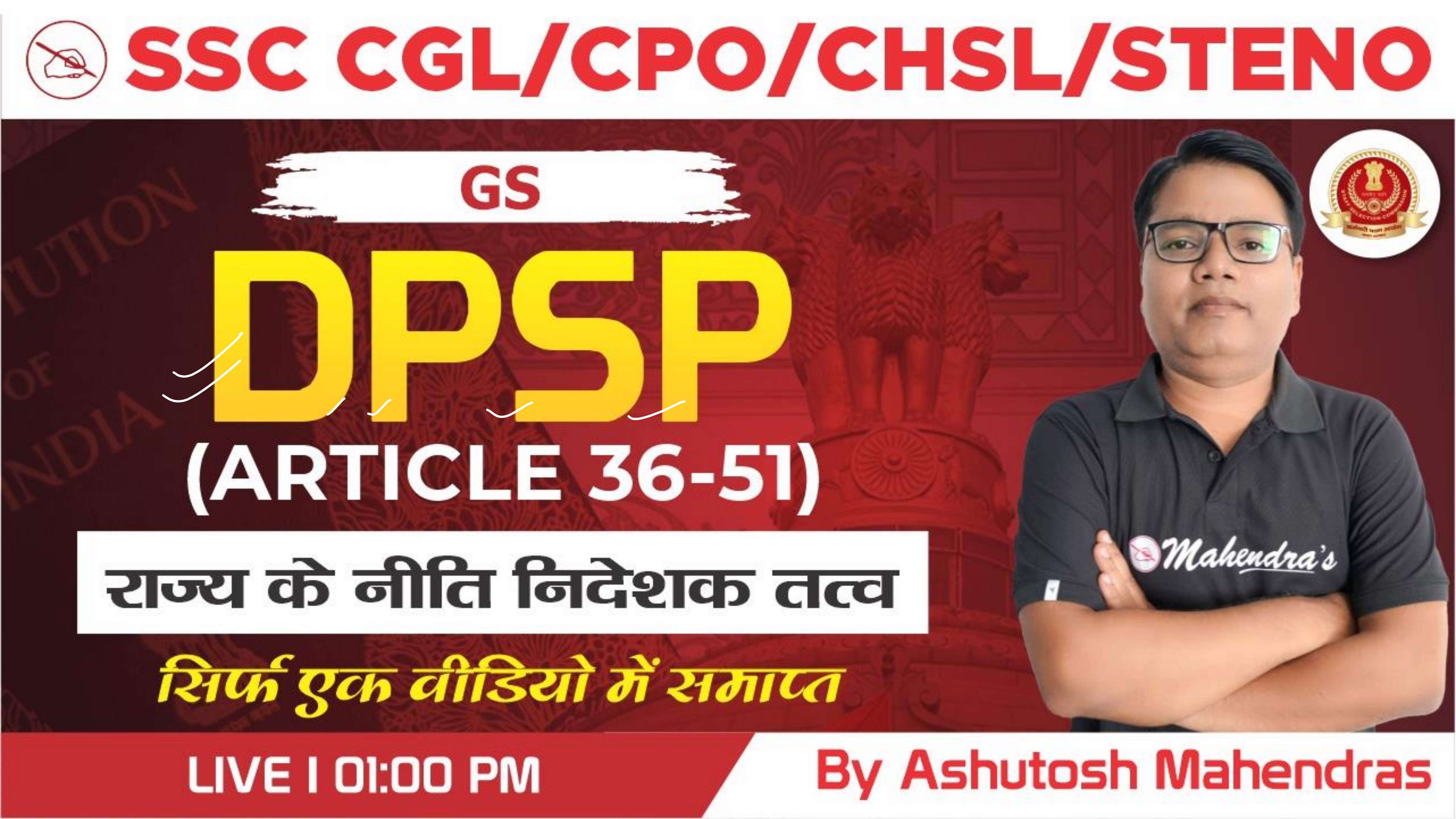
SSC CGL/CPO/CHSL/STENO
GS
DPSP
(ARTICLE 36-51)
राज्य के नीति निदेशक तत्व
सिर्फ एक वीडियो में समाप्त
LIVE I 01:00 PM
By Ashutosh Mahendras
Mahendra's

UPCOMING ONLINE BATCHES

September 2022

07 SEP 2022	14 SEP 2022	21 SEP 2022	28 SEP 2022
01:00 PM to 03:00 PM BANK ONLINE LIVE CLASS	08:00 AM to 10:00 AM BANK ONLINE LIVE CLASS	10:30 AM to 12:30 PM BANK ONLINE LIVE CLASS	07:30 PM to 09:30 PM BANK ONLINE LIVE CLASS
10:30 AM to 12:30 PM SSC ONLINE LIVE CLASS	05:30 PM to 07:30 PM SSC ONLINE LIVE CLASS	03:00 PM to 05:00 PM SSC ONLINE LIVE CLASS	08:00 AM to 10:00 AM SSC ONLINE LIVE CLASS
BILINGUAL	BILINGUAL	BILINGUAL	BILINGUAL

14 SEP 2022	28 SEP 2022
11:30 AM to 01:30 PM BANK ONLINE LIVE CLASS	04:00 PM to 06:00 PM BANK ONLINE LIVE CLASS
BENGALI+ENGLISH	BENGALI+ENGLISH

www.mahendras.org 7052477777/7052577777

राज्य के नीति निदेशक तत्व

अनुच्छेद 36-51 → DPSP

DPSP
(Article 36-51)

राज्य के नीति निदेशक तत्व

(Directive Principles of State Policy)

- राज्य के नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख संविधान के भाग-4 के अनुच्छेद 36 से 51 में किया गया है। संविधान निर्माताओं ने यह विचार 1937 में निर्मित आयरलैंड के संविधान से लिए।
- The Directive Principles of State Policy are mentioned in Article 36 to 51 of Part IV of the Constitution. The framers of the constitution took this idea from the constitution of Ireland made in 1937.

विशेषताएं (Characteristic)

FRs → प्रवर्तनीय

DPSP → गैर-प्रवर्तनीय

- राज्य की नीति के निर्देशक तत्व नामक इस उक्ति से यह स्पष्ट होता है कि नीतियों एवं कानूनों को प्रभावी बना समय राज्य इन तत्वों को ध्यान में रखेगा।
- From this statement called Directive Principles of State Policy, it is clear that the State will keep these elements in mind while making policies and laws effective.

- ये संवैधानिक निर्देश या विधायिका, कार्यपालिका और प्रशासनिक मामलों में राज्य के लिए सिफारिश है।
- These are constitutional directions or recommendations to the state in legislative, executive and administrative matters.

- इनका उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना है।
- Their aim is to build a 'Welfare State'.
- निदेशक तत्वों की प्रकृति गैर- न्यायोचित है। यानी कि उनके हनन पर उन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। अतः सरकार (केंद्र, राज्य एवं स्थानीय) इन्हें लागू करने के लिए बाध्य नहीं है।
- The Directive Principles are non-justiciable in nature. That is, they cannot be enforced by the court on their violation. Therefore, the government (Central, State and Local) is not bound to implement them.

→ Syllabus
→ PYQs
→ Cut-Off
→ Practice Test

निदेशक तत्वों का वर्गीकरण (DPSP Classification)

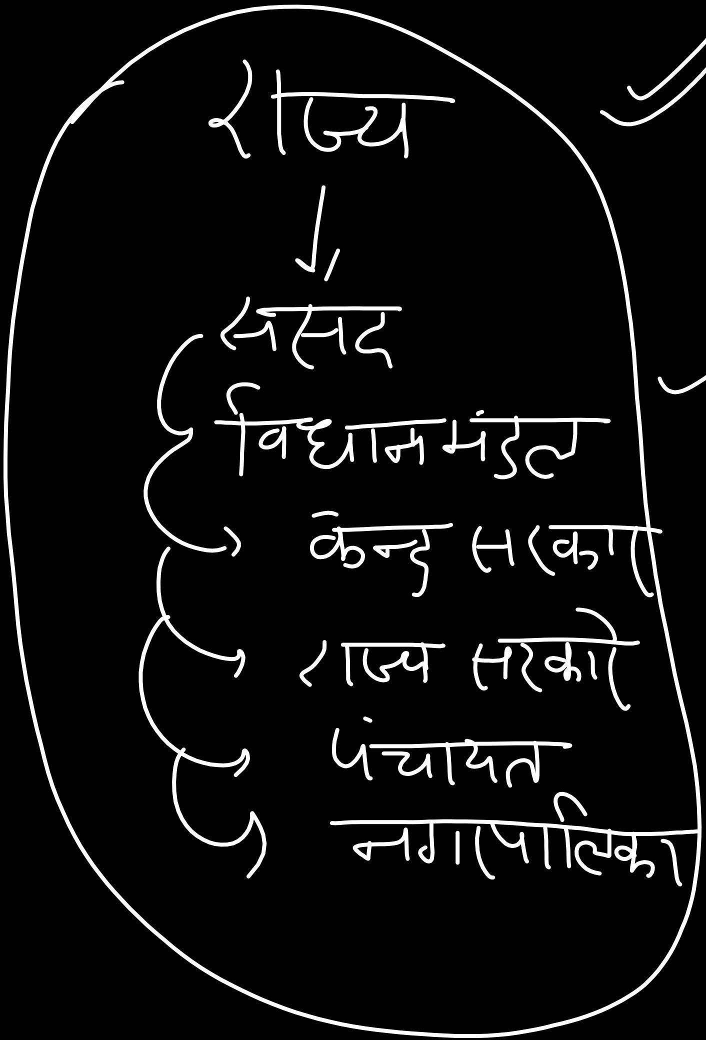

Article 36 - नीति निदेशक तत्त्वों के संदर्भ में 'राज्य' की परिभाषा । Definition of 'State' with reference to Directive Principles of Policy.

Article 37 - नीति निदेशक तत्त्वों को न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय (Enforceable) न होते हुए भी देश के शासन में मूलभूत माना गया है तथा विधि बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा । The Directive Principles of Policy, though not enforceable by the court, have been considered fundamental in the governance of the country and it will be the duty of the state to implement these principles in making laws.

Article 38

(1) सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय से परिपूर्ण व्यवस्था की स्थापना हो सके।

To establish a system full of social, economic and political justice.

(2) आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं तथा अवसरों की असमानताओं को समाप्त करने का प्रयास करना।

Inequalities of income, status, facilities and opportunities try to eliminate.

Article 39

राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व हैं Some of the policy elements to be followed by the state are –

(क) पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार (a) the right of all citizens, male and female, to have an adequate means of livelihood

(ख) समुदाय के भौतिक संसाधनों का उचित वितरण एवं स्वामित्व (b) Fair distribution and ownership of material resources of the community

(ग) उत्पादन के साधनों का विकेंद्रीकरण

(c) Decentralization of the means of production

(घ) स्त्रियों व पुरुषों को समान कार्य के लिये समान वेतन।

(d) Equal pay for equal work for men and women.

39(क) :समान अवसर के आधार पर न्याय देना व निः शुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराना, ताकि गरीबों को अन्याय का शिकार न होना पड़े। (42वें संविधान संशोधन अधिनियम,1976 द्वारा शामिल)

39(A): Providing justice on the basis of equal opportunity and providing free legal aid, so that the poor do not have to suffer injustice. (Incorporated by the 42nd Constitutional Amendment Act, 1976)

Article 40

- ग्राम पंचायतों का संगठन करना तथा उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने हेतु शक्तियाँ व प्राधिकार देना।
- To organize village panchayats and to give them powers and authority to function as units of self-government.

Article 41

वृद्धावस्था पेंशन

बेरोजगारी भत्ता

- कुछ दशाओं में विशेषत: बुढ़ापे, बेरोजगारी, बीमारी, अशक्तता आदि की दशा में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार सुनिश्चित करने के लिये राज्य प्रभावी प्रावधान करेगा।
- The State shall make effective provisions for ensuring the right to work, education and public assistance in certain conditions, especially in the case of old age, unemployment, disease, disability etc.

Q.1 कौन-से संविधान से राज्य नीति विषयक निदेशक तत्व अपनाए गए हैं?

The Directive Principles of State Policy has been adopted from which Constitution?

20

(a) अमेरिकी संविधान/ U.S. Constitution

(b) ब्रिटिश संविधान /British Constitution

(c) आइरिश संविधान /Irish Constitution

(d) फ्रांसीसी संविधान/ French Constitution

Q 2. भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन-सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए राज्य को निर्देश देता है ?

Which one of the following Articles of the Indian Constitution directs the State to ensure the right to adequate means of livelihood for the citizens?

20

(a) अनुच्छेद 33/Article 33

(b) अनुच्छेद 39 /Article 39

(c) अनुच्छेद 29/Article 29

(d) अनुच्छेद 27/ Article 27

Q 3. भारत के संविधान में निदेशक सिद्धांतों के शामिल किए जाने का मुख्य उद्देश्य क्या है?

What is the main objective of the inclusion of Directive Principles in the Constitution of India?

(a) सामाजिक-आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करने के लिए / To establish socio-economic democracy

(b) सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए/ To establish social democracy

(c) गांधीवादी लोकतंत्र स्थापित करने के लिए/ To establish Gandhian democracy

(a) राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित करने के लिए/ To establish a political democracy

Q.4 'कल्याणकारी राज्य' संबंधी विचार किसमें दिए गए हैं?

Ideas of 'Welfare State' are contained in-

DPSP

20

a) मूल अधिकार /Fundamental Rights

b) राज्य नीति संबंधी निदेशक सिद्धांत /Directive Principles of State Policy

c) संविधान की उद्देशिका /Preamble of the Constitution

d) भाग VII/Part VII

Q.5 भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत वर्णित हैं?

Directive principles of state policy are enumerated in which part of Indian Constitution?

20

a) Part I / भाग I

b) Part II / भाग II

c) Part III / भाग III

d) Part IV / भाग IV

DPSP

Art 36-51

Q.6 निम्नलिखित में से किसे विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है ?

Which of the following can be amended by special majority?

20

(a) राज्य के नीति निदेशक तत्व/DPSP

(b) संसद को चलाने के नियम/ Rules for running parliament

(c) नए राज्य का गठन/Formation of a new state

(d) संसद में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग/ Use of English language in Parliament

Q.7 राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं-

The Directive Principles of State Policy are-

20

Art 32 → SC

Art 226 → HCs

a) वाद योग्य/Enforceable

b) लचीले/Flexible

c) अवाद योग्य/Non-enforceable

d) कठोर/Rigid

Q.8 स्त्रियों और पुरुषों के लिए 'समान कार्य के लिए समान वेतन' का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है?

समानता

'Equal pay for equal work' for men and women is mentioned in which of the following articles?

20

(a) अनुच्छेद 33/Article 33

(b) अनुच्छेद 39 (क)/Article 39(A)

(c) अनुच्छेद 39(घ)/Article 39(D)

(d) अनुच्छेद 27/ Article 27

Q.9 ग्राम पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की प्रेरणा संविधान के किस अनुच्छेद से मिली?

Which article of the constitution got the inspiration to give constitutional status to village panchayats?

(a) अनुच्छेद 35/Article 35

(b) अनुच्छेद 36/Article 36

(c) अनुच्छेद 40/Article 40

(d) अनुच्छेद 45/ Article 45